भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
01.04.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 6153 का उत्तर

पीपीपी मॉडल के तहत ओडिशा में रेलवे स्टेशन

6153. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीपीपी मॉडल के तहत पुनर्विकास के लिए चुने गए ओडिशा के रेलवे स्टेशनों की संख्या, उन स्टेशनों की संख्या जहां पुनर्विकास कार्य शुरू हो चुका है/पूरा हो गया है और शेष परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, रेल मदद प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओडिशा से दर्ज की गई यात्री शिकायतों की संख्या, समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत और उनके निवारण में लगने वाला औसत समय क्या है;

(ग) 'एक स्टेशन एक उत्पाद' (ओएसओपी) योजना के तहत शामिल किए गए ओडिशा के रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है और आवंटित स्टालों की संख्या के साथ-साथ इन आउटलेट्स के माध्यम से बेचे जा रहे स्थानीय उत्पादों की श्रेणियां क्या हैं; और

(घ) पीएम गति शक्ति रेल साइडिंग नीति के तहत उक्त राज्य में रेल साइडिंग के लिए प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या, साथ ही चालू की गई साइडिंग की संख्या और इस नीति के तहत जुटाया गया निजी निवेश कितना है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित विभिन्न पद्धतियों का पता लगाया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु स्टेशनों के लिए उपयुक्तता निम्न कारकों जैसे परियोजनाओं की लागत, उपलब्ध राजस्व स्रोत, स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या, स्टेशन के आसपास का इलाका, शहर से संपर्कता आदि पर निर्भर करता है। अब तक, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति

स्टेशन को सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत विकसित करके कमीशन किया जा चुका है। वर्तमान में, सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत विकसित किए जाने हेतु 15 अदद स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। इन 15 स्टेशनों में से आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। अन्य 14 स्टेशन मास्टर प्लानिंग और वित्तीय मॉडलिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए अब तक 1,338 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 59 स्टेशन ओडिशा में स्थित हैं। ओडिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
ओडिशा	59	अंगुल, बादामपहाड़, बालंगीर, बालेश्वर, बालुगांव, बारबिल, बरगढ़ रोड, बारिपड़ा, बरपाली, बेलपहार, बेतनोटी, भद्रक, भवानीपटना, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर न्यू, बिमलागढ़, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, छत्रपुर, कटक, दामनजोड़ि, ढेंकानाल, गुनुपुर, हरिशंकर रोड, हिमगिर, हीराकुड, जाजपुर-केन्दुझर रोड, जलेश्वर, जारोली, जयपुर, झारसुगुड़ा जंक्शन, झारसुगुड़ा रोड, कांटाबंजि, केन्दुझरगढ़, केसिंगा, खरियार रोड, खोरदा रोड जंक्शन, कोरापुट जंक्शन, लिंगराज टेम्पल रोड, मंचेश्वर, मेरामंडली, मुनीगुड़ा, पानपोष, पारादीप, पारलखेमुंडी, पुरी, रघुनाथपुर, रैराखोल, रैरंगपुर, राजगंगपुर, रायगड़ा, राउरकेला, साक्षी गोपाल, संबलपुर, संबलपुर सिटी, सोरो, तालचेर, तालचेर रोड, टिटिलागढ़ जंक्शन।

ओडिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के तहत ओडिशा में 07 स्टेशनों (कटक, बारीपाड़ा, बारपाली, बिमलागढ़,

केसिंगा, परलाखेमुंडी, तालचर) का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर विकास कार्य भी अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और ओडिशा में स्थित कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:-

- भुवनेश्वर स्टेशन: पूर्व और पश्चिम की ओर नए स्टेशन भवन और एयर कॉनकोर्स के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर के स्टेशन पर एलिवेटेड ड्राइववे के संरचनात्मक कार्य, ऊपरी पैदल पुल और प्लेटफार्म शेल्टर के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्व और पश्चिम की ओर नए स्टेशन भवन के परिष्करण, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग), एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) और एस्केलेटर का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- पुरी स्टेशन: स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन का परिष्करण कार्य, प्लेटफार्म के उन्नयन और चारदीवारी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- बादामपहाड़ स्टेशन: प्लेटफार्म विस्तार और सतह का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए स्टेशन भवन, शौचालय ब्लॉक, परिचालन क्षेत्र, पार्किंग, पेयजल बूथ और प्रवेश/निकास का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- जरोली स्टेशन: नए प्रतीक्षालय सह बुकिंग काउंटर, शौचालय, पहुंच मार्ग, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- पानपोष स्टेशन: नए स्टेशन भवन, पहुंच मार्ग, परिचलन क्षेत्र और प्रवेश/निकास द्वार का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- राजगांगपुर स्टेशन: नए स्टेशन भवन और प्लेटफार्म की सतह का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लानिंग में शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण

- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म पर कवर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग का प्रावधान आदि शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार और स्टेशन/स्थिति/यातायात सम्भलाई आदि के आधार पर किए जाते हैं।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए अग्नि संबंधी मंजूरी, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना

रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस स्तर पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

<u>रेल मदद</u>

रेल मदद भारतीय रेल की शिकायत निवारण प्रणाली है जो यात्रियों को शिकायतों, सहायता और पूछताछ के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती है। रेल मदद में यात्री सहायता कई माध्यमों जैसे हेल्पलाइन नंबर-139, रेल मदद, वेब, ऐप और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रेल मदद यात्रियों को उनकी शिकायतों के निवारण पर प्रतिक्रिया साझा करने की भी अनुमति देता है।

<u>एक स्टेशन एक उत्पाद</u>

'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (ओएसओपी) योजना भारतीय रेल की एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत सरकार की 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करना और रेल यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत का अनुभव करने और स्थानीय/स्वदेशी उत्पाद खरीदने के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, भारतीय रेल पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर ओएसओपी आउटलेट्स (स्थायी स्टॉल/पोर्टेबल ट्रॉलियाँ) प्रदान करता है ताकि स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके, बेचा जा सके और उच्च दृश्यता मिल सके। इस योजना के तहत उत्पाद श्रेणियों में हस्तशिल्प/कला वस्तुएँ, वस्त्र और हथकरघा, पारंपरिक परिधान और स्थानीय कृषि उत्पाद/प्रसंस्कृत/अर्ध-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

28.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ओडिशा राज्य के 45 स्टेशनों पर कुल 55 ओएसओपी आउटलेट चालू थे। इन इकाइयों के माध्यम से बेचे जा रहे ओडिशा के स्थानीय उत्पादों में जनजातीय कला, जूट उत्पाद, कॉयर और हस्तनिर्मित उत्पाद, खुर्दा गमछा, लुंगी और बालाकटी पीतल, बांस उत्पाद, पट्टचित्र और पिपिली एप्लिक, संबलपुरी साड़ी और वस्त्र आदि शामिल हैं।

<u>गति शक्ति कार्गो टर्मिनल</u>

रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति शुरू की गई है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) निजी कंपनियों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, और इन्हें गैर-रेल भूमि पर या पूरी तरह से आंशिक रूप से रेल भूमि पर विकसित किया जा सकता है। जीसीटी का स्थान उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर तय किया जा रहा है। अब तक, 128 जीसीटीएस चालू किए जा चुके हैं (ओडिशा में 10 सहित) और इसके अलावा, 292 और जीसीटी स्थानों (ओडिशा में 35 स्थानों सहित) के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत, अब तक 128 चालू जीसीटी से लगभग 9183 करोड़ रुपए का निजी निवेश जुटाया गया है।

*****